



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 130]

नई दिल्ली, बुधवार, मई 18, 2005/वैशाख 28, 1927

No. 130]

NEW DELHI, WEDNESDAY, MAY 18, 2005/VAISAKHA 28, 1927

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(पाटनरोधी एवं संबद्ध शुल्क महानिदेशालय)

जांच शुरुआत संबंधी अधिसूचना

नई दिल्ली, 18 मई, 2005

विषय :—चीन जनवादी गणराज्य से 20-100 ग्रा./मीटर भार के सिल्क फेब्रिक्स के आयात से संबंधित पाटनरोधी जांच की शुरुआत।

सं. 14/20/2004-डीजीएडी.—केन्द्रीय रेशम बोर्ड, बंगलौर ने निम्नलिखित पावरलूम सिल्क फेब्रिक

उत्पादक सहकारी समितियों/परिसंघ/एसोसिएशनों अर्थात्

- (i) दि मैसूर पावर लूम सिल्क मेन्यूफैक्चरर्स को-ऑपरेटिव सोसायटी लि., बेंगलूर, कर्नाटक
- (ii) मै0 कर्नाटक वीवर्स फेडरेशन, बंगलौर कर्नाटक
- (iii) मै0 बंगलौर डिस्ट्रिक्ट एण्ड बंगलौर रूरल डिस्ट्रिक्ट पावरलूम वीवर्स प्रोडक्शन एंड सेल्स को-ओपरेटिव फेडरेशन लि., डोड्डा बाल्लापुर, कर्नाटक
- (iv) मै0 सिल्क ट्रेड एसोसिएशन (रजि.), वाराणसी, उ.प्र.
- (v) मै0 प्योर सिल्क वीवर्स एसोसिएशन, सूरत, गुजरात

के साथ वर्ष, 1995 में यथासंशोधित सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम 1975 और सीमाशुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं की पहचान, उन पर पाटनरोधी शुल्क का आकलन एवं संग्रहण और क्षति निर्धारण) नियमावली, 1995 के अनुसार निर्दिष्ट प्राधिकारी (जिन्हें इसके बाद प्राधिकारी कहा गया है) के समक्ष एक आवेदन दायर किया है जिसमें चीन जन. गण. से 20-100 ग्रा./मीटर भार के सिल्क फेब्रिक्स के पाटन का आरोप लगाया गया है और पाटनरोधी जांच शुरू करने तथा पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने का अनुरोध किया है।

विचाराधीन उत्पाद

2. वर्तमान याचिका में शामिल उत्पाद 20-100 ग्रा./मीटर भार का सिल्क फेब्रिक (जिसे इसके बाद संबद्ध वस्तु कहा गया है) है। सिल्क फेब्रिक का उत्पादन मूल कच्ची सामग्री अर्थात् कच्चे रेशम से किया जाता है। सिल्क फेब्रिक सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम शीर्ष 5007 के अंतर्गत वर्गीकृत है और यह सामान्यतः उपशीर्ष 5007 9000 में शामिल होता है। तथापि, आवेदकों का

यह दावा है कि संबद्ध वस्तु सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम के उपशीर्ष 5007 1000, 5007 20, 5007 2010 और 5007 2090 के अंतर्गत भी शामिल हो सकती है। ये वर्गीकरण मात्र सांकेतिक हैं और किसी भी तरह से वर्तमान जांच के कार्यक्षेत्र पर बाध्यकारी नहीं हैं।

समान वस्तु

3. याचिकाकर्ता ने दावा किया है कि भारत में पावरलूमों द्वारा उत्पादित सिल्क फैब्रिक संबद्ध देश के मूल के अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तु के समान वस्तु है। भारत में सिल्क फैब्रिक का उत्पादन हथकरघा द्वारा भी किया जाता है किन्तु उसे उत्पादन प्रक्रिया, कीमत एवं प्रतिस्थापनीयता जैसे मानदंडों के कारण संबद्ध देश से आयातित संबद्ध वस्तु के समान वस्तु नहीं माना गया है। तथापि, वर्तमान जांच के प्रयोजनार्थ, याचिकाकर्ता द्वारा पावरलूम क्षेत्र में उत्पादित सिल्क फैब्रिक को संबद्ध देश से आयातित संबद्ध वस्तु के "समान घरेलू वस्तु" माना जा रहा है।

घरेलू उद्योग

4. यह याचिका निम्नलिखित पावरलूम सिल्क फैब्रिक उत्पादक सहकारी समितियों/परिसंघ/एसोसिएशनों के साथ केन्द्रीय रेशम बोर्ड, बंगलौर द्वारा दायर की गयी है :-

- (i) दि मैसूर पावर लूम सिल्क मेन्यूफैक्चरर्स को-ऑपरेटिव सोसायटी लि., बेंगलूर, कर्नाटक
- (ii) मै0 कर्नाटक वीवर्स फेडरेशन, बंगलौर कर्नाटक
- (iii) मै0 बंगलौर डिस्ट्रिक्ट एण्ड बंगलौर रूरल डिस्ट्रिक्ट पावरलूम वीवर्स प्रोडक्शन एंड सेल्स को-ओपरेटिव फेडरेशन लि., डोड्डा बाल्लापुर, कर्नाटक
- (iv) मै0 सिल्क ट्रेड एसोसिएशन (रजि.), वाराणसी, उ.प्र.
- (v) मै0 प्योर सिल्क वीवर्स एसोसिएशन, सूरत, गुजरात

भारत में सिल्क फैब्रिक का उत्पादन हथकरघा द्वारा भी किया जाता है। तथापि, चूंकि इस जांच के प्रयोजनार्थ हथकरघा द्वारा उत्पादित सिल्क फैब्रिक को समान वस्तु नहीं समझा गया है, इसलिए घरेलू उद्योग के निर्धारण हेतु पावरलूमों द्वारा उत्पादित सिल्क फैब्रिक के उत्पादन पर विचार किया गया है। पावरलूमों की उपर्युक्त सहकारी समितियों/परिसंघ/एसोसिएशनों जिन्होंने स्पष्ट रूप से आवेदन का समर्थन किया है, का घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित समान उत्पाद के कुल उत्पादन में 50% से अधिक हिस्सा बनता है। पावरलूमों द्वारा उत्पादित सिल्क फैब्रिक के उत्पादकों की उपर्युक्त सहकारी समिति/परिसंघ/ एसोसिएशनों द्वारा भारत में पावरलूमों द्वारा उत्पादित सिल्क फैब्रिक के एक बड़े भाग का उत्पादन किया जाता है। प्राधिकारी यह निर्धारित करते हैं कि उक्त आवेदक नियम 5(3)(क) के अनुसार घरेलू उद्योग की ओर से आवेदन प्रस्तुत करने सम्बन्धी अर्हता को पूरा करते हैं और संबंधित नियमावली के नियम 2(ख) के अर्थ के भीतर घरेलू उद्योग का प्रतिनिधित्व करते हैं।

शामिल देश

5. वर्तमान जांच में शामिल देश चीन जनवादी गणराज्य है जिसे एतदपश्चात संबद्ध देश भी कहा गया है।

सामान्य मूल्य

6. याचिकाकर्ताओं ने यह दावा किया है कि चीन जन. गण. को पाटनरोधी जांचकर्ता प्राधिकारियों द्वारा गैर बाजार अर्थव्यवस्था माना गया है और इस प्रकार सामान्य मूल्य का निर्धारण समान उत्पाद की भारत में देय कीमत सहित अन्य किसी तर्कसंगत आधार पर किया जा सकता है। सिल्क फेब्रिक के अनुमानित सामान्य मूल्य का दावा प्रमुख कच्ची सामग्री अर्थात् कच्चे रेशम की लागत के आधार पर किया गया है। जो दिसम्बर 2003, मार्च 2004 और जून 2004 के इंटरनेशनल सिल्क एसोसिएशन (आईएसए), फ्रांस का मासिक समाचार पत्र पर आधारित है। सामान्य मूल्य का अनुमान लगाने के लिए तर्कसंगत परिवर्तन लागत, प्रशासनिक, बिक्री सम्बन्धी, सामान्य व्ययों तथा लाभ को जोड़ा गया है। प्राधिकारी पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध I के पैराग्राफ 7 और 8 के अनुसार सामान्य मूल्य के दावे की जांच का प्रस्ताव करते हैं। प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि चीन जन. गण. से संबद्ध वस्तु के लिए दावा किए गए सामान्य मूल्य के पर्याप्त साक्ष्य हैं।

निर्यात कीमत

7. निर्यात कीमत 5007 9000 शीर्ष के अंतर्गत डीजीसीआईएंडएस के आंकड़ों पर आधारित है। कारखाना द्वार पर निर्यात कीमत निकालने के लिए समुद्री भाड़े, बीमा, अंतर्देशीय भाड़े, भंडारण इत्यादि के संबंध में समायोजनों का दावा किया गया है। संबद्ध देश से संबद्ध वस्तु के लिए दावा की गई निर्यात कीमत का पर्याप्त साक्ष्य है।

पाटन मार्जिन

8. इस बात का प्रथम दृष्ट्या साक्ष्य है कि संबद्ध देश में संबद्ध वस्तु का सामान्य मूल्य कारखाना द्वार पर निर्यात कीमत से काफी अधिक है जिससे प्रथम दृष्ट्या यह संकेत मिलता है कि संबद्ध देश के निर्यातकों द्वारा संबद्ध वस्तु का पाटन किया जा रहा है।

क्षति एवं कारणात्मक संबंध

9. आवेदकों ने क्षति से संबंधित विभिन्न मापदण्डों सम्बन्धी सूचना प्रस्तुत की है। उत्पादन में भारी गिरावट, क्षमता उपयोग में कमी, अनेक पावरलूमों का बंद होना, बिक्री में कमी, रोजगार में गिरावट, मांग के बाजार हिस्से में गिरावट, लाभप्रदता में कमी, बिक्री वसूली में गिरावट, कीमत कटौती और घरेलू उद्योग को हुए घाटे जैसे मापदण्ड प्रथम दृष्ट्या समग्र रूप से यह संकेत करते हैं कि घरेलू उद्योग को पाटन के कारण वास्तविक क्षति उठानी पड़ी है। अन्य देशों से संबद्ध वस्तु के आयात नगण्य हैं। संबद्ध देश से आयातों के हिस्से में समग्र रूप से तथा भारत में उत्पाद की मांग की तुलना में वृद्धि हुई है। प्रथम दृष्ट्या साक्ष्य संबद्ध वस्तु के पाटित आयातों और घरेलू उद्योग को हुई क्षति के बीच में कारणात्मक संबंध को दर्शाते हैं।

पाटनरोधी जांच का आरंभ

10. उपरोक्त पैराग्राफों को देखते हुए निर्दिष्ट प्राधिकारी, संबद्ध देशों के मूल की या वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तु के कथित पाटन की मौजूदगी, उसकी मात्रा तथा उसके प्रभाव की पाटनरोधी जांच आरंभ करते हैं।

जांच की अवधि (पीओआई)

11. वर्तमान जांच के प्रयोजनार्थ जांच की अवधि 1 अप्रैल, 2003 से 30 सितम्बर, 2004 (18 महीने) तक की है।

सूचना देना

12. संबद्ध देशों के निर्यातकों और भारत में इस जांच से जुड़े ज्ञात संबद्ध आयातकों को संबंधित सूचना निर्धारित रूप में और निर्धारित ढंग से देने और अपने विचारों से निर्दिष्ट प्राधिकारी, पाटनरोधी एवं संबद्ध शुल्क महानिदेशालय, वाणिज्य विभाग, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार, उद्योग भवन, नई दिल्ली- 110011 को अवगत कराने के लिए अलग से लिखा जा रहा है। अन्य कोई हितबद्ध पार्टी भी नीचे दी गई समयावधि के भीतर निर्धारित रूप में और निर्धारित ढंग से जांच से संबंधित अभिवेदन दे सकती है।

समय सीमा

13. वर्तमान जांच से संबंधित कोई भी सूचना लिखित रूप में दी जाए जो उपरोक्त पते पर निर्दिष्ट प्राधिकारी के पास इस अधिसूचना के प्रकाशित होने की तारीख से 40 दिनों के भीतर पहुँच जानी चाहिए। तथापि, जिन ज्ञात निर्यातकों और आयातकों को अलग से लिखा जा रहा है, उन्हें अलग से लिखे गए पत्र की तारीख से 40 दिनों के भीतर सूचना देनी होगी।

सार्वजनिक फाइल का निरीक्षण

14. नियम 6(7) के अनुसार कोई भी हितबद्ध पार्टी उस सार्वजनिक फाइल का निरीक्षण कर सकती है जिसमें अन्य हितबद्ध पार्टियों द्वारा प्रस्तुत किए गए साक्ष्यों के अगोपनीय अंश रखे गए हैं।

यदि कोई हितबद्ध पार्टी आवश्यक सूचना देने से मना करती है या उचित समय के भीतर उसे अन्यथा उपलब्ध नहीं कराती है या प्रभावी रूप से जांच में बाधा डालती है तो प्राधिकारी, अपने पास उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपने जांच परिणाम दर्ज कर सकते हैं और केन्द्रीय सरकार को यथोचित सिफारिशें कर सकते हैं।

क्रिस्टी एल. फेर्नंडेज, निर्दिष्ट प्राधिकारी

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY**(Department of Commerce)****(DIRECTORATE GENERAL OF ANTI-DUMPING AND ALLIED DUTIES)****INITIATION NOTIFICATION**

New Delhi, the 18th May, 2005

Subject :—Initiation of Anti-dumping investigation concerning import of Silk Fabrics 20-100 gms/meter from People's Republic of China.

No. 14/20/2004-DGAD.— Central Silk Board, Bangalore along with the following co-operative / federation / associations of power loom silk fabric producers viz.

- (i) The Mysore Power Loom Silk Manufacturers Co-operative Society Ltd., Bangalore, Karnataka.
- (ii) M/s Karnataka Weavers Federation, Bangalore, Karnataka.
- (iii) M/s Bangalore District and Bangalore Rural District Power-Loom Weavers Production and Sales Co-operative Federation Ltd., Dodda Ballapur, Karnataka.
- (iv) M/s Silk Trade Association (Regd), Varanasi, UP.
- (v) M/s Pure Silk Weavers Association, Surat, Gujarat.

have filed an application in accordance with the Customs Tariff Act, 1975 as amended in 1995 and Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti Dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995 before the Designated Authority (hereinafter referred to as the Authority) alleging dumping of Silk Fabrics of weight 20-100 gms/meter from People's Republic of China and requested for Anti Dumping investigations and levy of anti dumping duties.

PRODUCT UNDER CONSIDERATION

2. The product involved in the present investigation is Silk Fabric of weight 20-100 gms/meter (hereinafter also referred to as subject goods). Silk fabric is produced from the basic raw material raw silk. Silk Fabric is classified under Heading 5007 of the Customs Tariff Act and generally gets covered under Sub-heading 5007 9000. However, applicants have claimed that the subject goods may also get covered under Sub-headings 5007 1000, 5007 20, 5007 2010 and 5007 2090 of the Customs Tariff Act. These Classifications are indicative only and are in no way binding on the scope of the present investigation.

LIKE ARTICLE

3. The applicants have claimed that the silk fabric produced by the power looms in India is like article to the subject goods originating in or exported from subject country. Silk Fabric is also produced in India in handlooms, which has, however, not been treated as like article to the subject goods being imported from subject country on account of parameters like production process, price and substitutability. Therefore, for the purpose of the present investigation, the silk fabric produced by the applicants in power loom sector only is being

1541 GI/05-2

treated as 'Domestic Like Article' to the subject goods being imported from the subject country.

DOMESTIC INDUSTRY

4. The application has been filed by the Central Silk Board, Bangalore along with the following co-operative / federation / associations of power loom silk fabric producers viz.

- (i) The Mysore Power Loom Silk Manufacturers Co-operative Society Ltd., Bangalore, Karnataka.
- (ii) M/s Karnataka Weavers Federation, Bangalore, Karnataka.
- (iii) M/s Bangalore District and Bangalore Rural District Power-Loom Weavers Production and Sales Co-operative Federation Ltd., Dodda Ballapur, Karnataka.
- (iv) M/s Silk Trade Association (Regd), Varanasi, UP.
- (v) M/s Pure Silk Weavers Association, Surat, Gujarat.

Silk fabric is also produced on handlooms in India. However, the silk fabric produced on hand looms being not considered as like article for the purpose of this investigation, the production of silk fabric in power looms has been considered for determining the domestic industry. The aforesaid co-operative / federation / associations of power looms expressly supporting the application account for more than 50 percent of total production of the like article produced by the domestic industry. The aforesaid co-operative / federation / associations of power looms producing silk fabric represent a major proportion of silk fabric produced in India in power looms. The Authority determines that aforesaid applicants satisfy the criteria of standing to file the application on behalf of the domestic industry in terms of Rule 5(3)(a) and represent the domestic industry within the meaning of Rule 2 (b) of the Rules supra.

COUNTRY INVOLVED

5. The country involved in the present investigation is People's Republic of China hereinafter also referred to as the subject country.

NORMAL VALUE

6. Applicants have claimed that PR China has been treated as non-market economy by anti dumping Investigating Authorities and as such normal value may be determined on a reasonable basis including the price payable in India for the like product. The estimated normal value of Silk Fabric has been claimed on the basis of the cost of major raw material raw silk, which is based on International Silk Association (ISA), France monthly newsletter, December 2003, March 2004 and June 2004. Reasonable conversion cost, administrative, selling, general expenses and profit has been added to arrive at the estimate of normal value. The Authority proposes to examine the normal value claim as per paragraph 7 & 8 of Annexure I of Anti Dumping Rules. The Authority notes that there is sufficient evidence of the Normal value claimed for the subject goods from China P R.

EXPORT PRICE

7. The export price has been based on DGCI&S data under heading 5007 9000. Adjustments have been claimed on account of ocean freight, insurance, inland freight, storage

etc. to arrive at the Export Price at ex-factory level. There is sufficient evidence of the export price claimed for the subject goods from the subject country.

DUMPING MARGIN

8. There is prima facie evidence that the Normal Value of the subject goods in the subject country is significantly higher than the ex-factory export price indicating prima-facie that the subject goods are being dumped by exporters from the subject country.

INJURY AND CAUSAL LINK

9. The applicants have furnished information on various parameters relating to injury. Parameters such as significant decline in production, decline in capacity utilization, closure of several power looms, decline in sales, drop in employment, loss of market share in demand, decline in profitability, decline in the sales realization, price undercutting, and losses to the Domestic Industry prima-facie indicate collectively that the Domestic Industry has suffered material injury on account of dumping. Imports from other countries of subject goods are negligible. The share of imports from subject country has increased in absolute terms as well as in relation to the demand of the product in India. The prima facie evidence shows causal link between the dumped imports of the subject goods and injury caused to the domestic industry.

INITIATION OF ANTI-DUMPING INVESTIGATIONS

10. The Designated Authority, in view of the foregoing paragraphs, initiates anti-dumping investigations into the existence, degree and effect of alleged dumping of the subject goods originating in or exported from the subject country.

PERIOD OF INVESTIGATION (POI)

11. The period of investigation for the purpose of present investigation is 1st April 2003 to 30th September 2004 (eighteen months).

SUBMISSION OF INFORMATION

12. The exporters in the subject country and the importers in India known to be concerned with this investigation are being addressed separately to submit relevant information in the form and manner prescribed and to make their views known to the Designated Authority, Directorate General of Anti Dumping & Allied Duties, Department of Commerce, Ministry of Commerce & Industry, Government of India, Udyog Bhavan, New Delhi-110011. Any other interested party may also make its submissions relevant to the investigation in the prescribed form and manner within the time limit set out below.

TIME LIMIT

13. Any information relating to the present investigation should be sent in writing so as to reach the Authority at the address mentioned above not later than forty days from the date of publication of this notification. The known exporters and importers, who are being addressed

separately, are however, required to submit the information within forty days from the date of the letter addressed to them separately.

INSPECTION OF PUBLIC FILE

14. In terms of Rule 6(7), any interested party may inspect the public file containing non-confidential version of the evidence submitted by other interested parties.

In case where an interested party refuses access to, or otherwise does not provide necessary information within a reasonable period, or significantly impedes the investigation, the Authority may record its findings on the basis of the facts available to it and make such recommendations to the Central Government as deemed fit.

CHRISTYL L. FERNANDEZ, Designated Authority